जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है।
– अज्ञात

फिल्म इंडस्ट्री में काफी गर्मागर्मी

सच कहें तो बॉलिवुड के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री सरकार समर्थक और विरोधी खेमों में बंटी नजर आ रही है।

अमित शर्मा।

सीएए, एनआरसी और जेएनयू–जामिया हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काफी गर्मागर्मी देखी जा रही है। इसका एक नमूना अभी दो बड़े एक्टरों की तीखी नोकझोंक में दिखा। नसीरुद्दीन शाह ने एक आयोजन में अनुपम खेर को 'जोकर' बताते हुए कहा कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जवाब में अनुपम खेर ने शाह को कुंठित अभिनेता बताया।

दरअसल शाह और खेर में टकराहट की वजह सरकार के कुछ हालिया फैसले हैं। शाह सीएए और संभावित एनआरसी की आलोचना कर रहे हैं, जबकि खेर इनका समर्थन कर रहे हैं। सच कहें तो बॉलिवुड के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री सरकार समर्थक और विरोधी खेमों में बंटी नजर आ रही है। बहुत सारे मुद्दों पर नसीरुद्दीन शाह के अलावा अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, अनुभव सिन्हा, दीपिका पादुकोण, फरहान अख्तर, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर और अनुराग बसु जैसे लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ अनुपम खेर, कंगना रनौत, परेश रावल, विवेक ओबरॉय, प्रसून जोशी, मधुर भंडारकर और विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग खुलकर सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को गलत बता रहे हैं। दो बड़े सितारे अक्षय कुमार और अजय देवगन सरकार के करीबी माने जाते हैं लेकिन तीखी बहसों में जाने से बचते हैं।

बॉलिवुड ने राजनीतिक सवालों पर कई अच्छी फिल्में पेश की हैं, लेकिन इनसे जुड़े लोग राजनीतिक सक्रियता से बचते रहे हैं। इमरजेंसी और उसके तुरंत बाद वाले दौर में भी देवानंद, विजय आनंद, किशोर कुमार सरीखे अपवादों को छोड़ दें तो फिल्मी दुनिया लगभग तटस्थ ही रही। बॉलिवुड में राजनीतिक सवालों पर सीधी सक्रियता 2014 के चुनाव के दौरान देखी गई, जब लगभग 60 फिल्मी हस्तियों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट देने की अपील की थी। इस पर कई कलाकारों ने ऐतराज जताया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही बॉलिवुड में विभाजन गहराता गया। अनुपम खेर और गायक अभिजीत ने जैसे सरकार के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया और वे सत्तारूढ़ दल के हर कदम का बचाव करने लगे। 2019 के चुनाव में बॉलिवुड की कई हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में खुली अपील जारी की। माना जाता है कि कला–साहित्य प्रायरू सत्ता विरोधी होता है। हॉलिवुड में यह रुझान काफी मुखर रहा है। वहां रॉबर्ट डि नीरो और मेरिल स्ट्रीप जैसे सुपर स्टार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की खुली आलोचना की है। उनके पहले सूसन सैरॉनडॉन और गैब्रियल बर्न बुश प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। लेकिन बॉलिवुड में इस बार का विभाजन असाधारण है। हर मामले में उसके पीछे चलने वाला भारतीय समाज इससे कितना प्रभावित होता है, समय बताएगा।

अपना दीपक खुद बनें

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

दूसरे प्रकार का सवाल आत्म, आत्मा, ब्रह्म या परम वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है। बुद्ध तब मौन हो गए जब उन्होंने ऐसे सवालों का सामना कियारू क्या आत्म होता है, या नहीं होता? वह मौन रहे क्योंकि ये सवाल प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित है, तर्क से परे है और केवल अंतर्ज्ञान द्वारा समझा जा सकता है। ये तर्कमूलक ज्ञान से संबंधित नहीं है।

हालांकि, बुद्ध के मौन का मतलब ये नहीं था कि वह किसी स्थायित्व के अस्तित्व से इनकार कर रहे हों। एक उपदेश में वे कहते हैंरू "अजन्म, बेनाम होता हैय यदि वह वहां नहीं है, तो जीवन, नाम की दुनिया से बाहर नहीं जा सकता था।" इसलिए बुद्ध सलाह देते हैं "अपना दीपक खुद बनें।

संपादकीय

मतभेदों को कम करना

लगभग 50 वर्ष पहले जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्लूईएफ) की स्थापना हुई तो इसे 'यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम' कहा जाता था। इसके संस्थापक क्लॉस श्वाब का लक्ष्य था यूरोप की कंपनियों को अमेरिकी मैनेजमेंट के तौर–तरीकों से परिचित करवाना। इसकी पहली मीटिंग में पश्चिमी यूरोप की कंपनियों के 444 टॉप अधिकारियों को निमंत्रण भेजा गया था। पर धीरे–धीरे इन मीटिगों का उद्देश्य महज मैनेजमेंट ट्रेनिंग न होकर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक–सामाजिक मुद्दों पर बातचीत और आपसी मतभेदों को कम करना हो गया।

सच कहें तो डब्ल्यूईएफ एक एनजीओ है, जिसके सदस्यों में दुनिया के बड़े–बड़े कॉर्पोरेशंस शामिल हैं। इसका घोषित मिशन है– 'समाज के व्यापारिक, राजनीतिक, अकादमिक और अन्य नेताओं का विचार–विनिमय, ताकि विश्व की स्थिति में सुधार हो।' यहां कॉरपोरेट घरानों के सीईओज के अतिरिक्त ट्रंप और मोदी, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी सिलेब्रिटीज, संभ्रात पत्रकारों और बैंकरों की भागीदारी भी होती है। इस बार की बैठक में इसके संस्थापक क्लास श्वाब ने आह्वान किया है कि पूंजीपतियों को अपने शेयरहोल्डरों के हितों से ऊपर उठकर सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को देखना चाहिए। अगस्त 2019 में अमेरिका में हुई बिजनेस राउंड टेबल की मीटिंग में, जिसमें टॉप के अमेरिकी कॉरपोरेट्स शामिल थे, इस बात पर जोर दिया गया था कि कंपनियों को अपने लाभ के अलावा अपने कर्मचारियों के भविष्य में भी निवेश करना चाहिए और करीबी समुदायों की मदद करनी चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की बातें करना कॉरपोरेट्स का शगल रहा है। वही पुरानी बातें हर बैठक में रीपैकेज करके पूंजीवाद में सुधार लाने की बात दावोस–2020 के अजेंडे पर भी है।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इस प्रक्रिया पर अमल करने वाले सरकारी अमले को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह लोगों को 'संदिग्ध नागरिक' की श्रेणी में डाल दे।

कानून के विरोध में याचिका

नवीन जोशी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर देश में जिस तरह का ध्रुवीकरण है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने इस एक मामले में 144 याचिकाएं दायर होना अटपटा नहीं लगता। कोर्ट से जल्दी कोई आदेश मिल जाने की उम्मीद भी समझ में आती है। लेकिन इस कानून के विरोध और समर्थन में जुटे लोगों को इतनी ही समझदारी सुप्रीम कोर्ट के रवैये को लेकर भी दिखानी चाहिए, जिसकी तीन सदस्यीय बेंच ने तत्काल इसके अमल पर रोक लगाने या इसे ज्यादा बड़ी बेंच के पास भेजने का रास्ता नहीं अपनाया और सरकार को इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया। कानून के विरोध में याचिका लगाने वालों की चिंता एक पहलू से काफी ठोस लगती है।

अदालत को बताया गया कि एनपीआर (नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) की प्रक्रिया आगामी अप्रैल में ही शुरू होनी है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इस प्रक्रिया पर अमल करने वाले सरकारी अमले को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह लोगों को 'संदिग्ध नागरिक' की श्रेणी में डाल दे। जिसके नाम के सामने यह निशान लग गया, उसकी मदद करने के लिए कोई गाइडलाइन भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह दलील सुनने

के बाद भी सीएए का अनुपालन निलंबित रखने का आग्रह स्वीकार नहीं किया तो इसकी दो वजहें हैं। एक तो यह कि अभी तुरंत यह किसी के लिए जीवन–मरण का प्रश्न नहीं बनने जा रहा। दूसरे, यह कानून संवैधानिक तरीके से, यानी संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल करने के बाद लागू हो रहा है, यानी देश का सामूहिक विवेक इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है।

सरकार का पक्ष सुने बगैर इस बारे में कुछ कहना एक खराब परंपरा की शुरुआत करने जैसा ही था। देश की आबादी का एक हिस्सा अगर इस कानून में कोई गड़बड़ी महसूस कर रहा है तो उसे विरोध प्रदर्शन से आगे बढ़कर देश के सामूहिक विवेक में बदलाव लाने का जतन करना चाहिए। यह काम इतना बड़ा है कि इसमें किसी जल्दबाजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सही है कि सीएए के खिलाफ पिछले एक महीने से देश के कई शहरों में विभिन्न तरीकों से ऐतराज जताया जा रहा है। कुछ शुरुआती घटनाओं को छोड़ दें तो यह विरोध शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा है। इसके बावजूद सचाई यही है कि देश की विशाल जनसंख्या का कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा इस बहस से अछूता है।

सत्तापक्ष ने अपनी तरफ से लोगों के बीच जाकर उन्हें सीएए के बारे में बताने की सराहनीय पहल की है। इसका विरोध कर रहे लोगों के पास भी मौका है कि वे अपना पक्ष लोगों को बताएं। अदालत इस बारे में आगे अपना फैसला सुनाएगी ही, लेकिन इस बीच अगर भारत की नागरिकता और इससे जुड़ी नई शर्तों को लेकर दोनों पक्षों की ओर से बातें लोगों के बीच जाएं तो इस क्रम में भारतीय लोकतंत्र पहले से अधिक समृद्ध होगा।

अष्टयोग- 4929

4	2		3	5	1	
2	32	4	39	7	34	4
	1		4		5	2
	30	3	38	6	31	
1	2		6		7	
3	27	2	25	1	31	
	6	1	4		3	5

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4928 का हल

7	6	1	4	2	3	5
2	28	4	33	7	35	4
1	2	5	6	4	7	3
5	28	3	38	6	34	1
4	2	6	3	5	1	7
3	31	2	31	1	30	6
6	1	7	4	3	5	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

इंसान एक डेटा सेटर में परिवर्तित

मुकुल श्रीवास्तव। भारत में हैलो, टिकटॉक और वीगो वीडियो की स्वामित्व वाली कंपनी बाइट डांस के करीब 25 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इस कंपनी ने कारोबारी साल 2019 में 3.4 करोड़ का मुनाफा कमाया। जैउबा कॉर्प के हिसाब से इस कंपनी के भारत में 10 से कम कर्मचारी हैं। लिंक्डइन के भारत में मात्र 750 कर्मचारी हैं। साफ है कि सोशल मीडिया साइट्स में प्रत्यक्ष रोजगार बहुत ही कम हैं और इनकी ज्यादातर आमदनी यूजर सेंट्रिक विज्ञापन से होती है। ज्यादातर साइट्स फ्री हैं इसलिए उपभोक्ता फ्री यूज की कीमत अपनी निजी जानकारी से चुकाते हैं।

असल में इंसान एक डेटा सेट (आंकड़े का पुलिंदा) में परिवर्तित हो गया और इससे मूल्यवान आज कोई चीज नहीं है। जो चीज हमें मुफ्त दिखाई दे रही है वह सुविधा हमें हमारे संवेदनशील निजी डेटा के बदले मिल रही है। कंपनियों की आमदनी का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों से आता है और आप क्या विज्ञापन देखेंगे इसके लिए आपके व्यक्तित्व को जानना जरूरी है।